Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

27 सितम्बर 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास पर DSIR/CSIR योजना को मंज़ूरी दी।

सितंबर 2025 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (DSIR/CSIR) की "क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (CB&HRD)" योजना को मंज़ूरी दी।

- **- यह योजना विश्वविद्यालयों, उद्योगों, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों में करियर बनाने के इच्छुक युवा शोधकर्ताओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणितीय विज्ञान के क्षेत्रों के प्रख्यात वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में एक व्यापक मंच प्रदान करती है।**

- **इस पहल को 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के लिए 2,277.397 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी गई है।**

Key Points:-

(i) इस योजना का कार्यान्वयन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा किया जाएगा, जिसमें अनुसंधान एवं विकास संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान और भारत भर के विश्वविद्यालय शामिल होंगे।

(ii) इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल शोधकर्ताओं का एक मजबूत समूह तैयार करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में नवाचार-आधारित विकास को गति देना है।

2. कैबिनेट समिति ने बिहार में प्रमुख राजमार्ग और रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी।

सितंबर 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाने, यात्रा समय को कम करने और राज्य में आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी।

- **पहली परियोजना में हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)-139W के चार लेन वाले साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड का निर्माण शामिल है।**

- **यह परियोजना 78.942 किलोमीटर लंबी है, जिसकी अनुमानित पूंजी लागत 3,822.31 करोड़ रुपये है। यह परियोजना पटना और बेतिया के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करेगी तथा उत्तर बिहार के कई जिलों को जोड़ेगी।**

• नया NH-139W राजमार्ग वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सहित विभिन्न जिलों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार लाएगा और भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुँच को बढ़ाएगा। इससे क्षेत्र में परिवहन और व्यापार में सुगमता आने की उम्मीद है।

Key Points:-

(i) स्वीकृत दूसरी परियोजना बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेल लाइन का दोहरीकरण है, जिसकी कुल लागत 2,192 करोड़ रुपये है। यह परियोजना रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण करेगी और राज्य में बढ़ती यात्री एवं माल ढुलाई की माँग को पूरा करेगी।

(ii) बिहार के चार ज़िलों को कवर करते हुए, बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण से भारतीय रेल नेटवर्क का लगभग 104 किलोमीटर विस्तार होगा। इस परियोजना से भीड़भाड़ कम होगी, यात्रा का समय कम होगा और रेलवे की परिचालन दक्षता में सुधार होगा।

(iii) ये राजमार्ग और रेलवे पहल मिलकर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के व्यापक दृष्टिकोण के तहत बिहार में आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

3. प्रधानमंत्री मोदी ने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और 65,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की।

24 सितंबर, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेज़ी लाने के उद्देश्य से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित प्लेटफ़ॉर्म, प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में खनन, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारे और बिजली जैसे क्षेत्रों में फैली आठ महत्वपूर्ण पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनका कुल मूल्य ₹65,000 करोड़ से अधिक है।

• समीक्षा की गई परियोजनाएं 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती हैं, जो बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास को दर्शाती हैं।

• प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजनाओं की समय-सीमा का पालन करने के महत्व पर ज़ोर दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि देरी से लागत बढ़ती है और नागरिक आवश्यक सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने परियोजनाओं का शीघ्र और कुशल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।

• बैठक में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि बाधाओं का शीघ्र समाधान किया जा सके। बड़े पैमाने की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Key Points:-

(i) समीक्षाधीन परियोजनाएँ खनन, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारे और बिजली सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। यह विविधीकरण व्यापक बुनियादी ढाँचे के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

(ii) प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता को समय पर सेवाएँ प्रदान करने में भी बाधा आती है। उन्होंने इस तरह की देरी को कम करने और परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।

4. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस और चिकित्सा शिक्षा क्षमता के विस्तार को मंजूरी दी।

24 सितंबर, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और पूरे भारत में चिकित्सा शिक्षा क्षमता का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रमुख प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। ये निर्णय रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस (PLB) के वितरण और देश भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण को मज़बूत करने के लिए स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) दोनों चिकित्सा सीटों को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

- **केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.91 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर 1,865.68 करोड़ रुपये की PLB राशि के वितरण को मंज़ूरी दे दी है। पीएलबी का उद्देश्य भारतीय रेल की दक्षता और समग्र उत्पादन में सुधार हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है।**

- **प्रत्येक कर्मचारी को देय अधिकतम PLB 17,951 रुपये है। यह ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप 'सी' कर्मचारियों सहित सभी श्रेणियों को प्रदान किया जाएगा। यह बोनस दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टियों से पहले प्रतिवर्ष दिया जाता है।**

- **यह घोषणा भारतीय रेलवे द्वारा रिकॉर्ड परिचालन प्रदर्शन के बाद की गई है, जिसने वित्तीय वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 25) में 1,614.90 मिलियन टन (MT) कार्गो लोड किया और 7.3 बिलियन यात्रियों को ढोया।**

Key Points:-

(i) मंत्रिमंडल ने मौजूदा राज्य और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र पीजी संस्थानों और सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इससे देश भर में 5,000 अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटें सृजित होंगी।

(ii) कैबिनेट ने मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाने के लिए CSS के विस्तार को भी मंज़ूरी दे दी है, जिससे 5,023 स्नातक सीटें जुड़ जाएँगी। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और नई चिकित्सा विशेषज्ञताएँ शुरू करने के उद्देश्य से प्रति सीट बढ़ी हुई लागत सीमा 1.50 करोड़ रुपये निर्धारित की गई

है।

(iii) इन योजनाओं का अनुमानित बजट 2025-26 से 2028-29 तक 15,034.50 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 10,303.20 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 4,731.30 करोड़ रुपये है। भारत में वर्तमान में 808 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 1,23,700 एमबीबीएस सीटें (127% वृद्धि) और 43,041 पीजी सीटें (143% वृद्धि) हैं, जो चिकित्सा शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।

5. CAG ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और कर प्रशासन को बढ़ाने के लिए CBDT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

23 सितंबर, 2025 को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय ने नई दिल्ली, दिल्ली में राजस्व विभाग (DoR), वित्त मंत्रालय (MoF) के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- **इस सहयोग का उद्देश्य प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के माध्यम से लेखा परीक्षा, कराधान और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में परिचालन प्रभावशीलता में सुधार करना है।**
- **इस समझौता ज्ञापन पर CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल और उप CAG आनंद मोहन (A.M) बजाज ने के संजय मूर्ति, CAG की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, जो दोनों संगठनों के बीच संस्थागत सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।**

Key Points:-

(i) यह साझेदारी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, लेखा परीक्षा और कर प्रशासन में दक्षता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। यह लेखा परीक्षा और कर प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और गति में सुधार के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को अपनाने पर ज़ोर देती है।

(ii) समझौता ज्ञापन में प्रशिक्षण कार्यशालाओं, संयुक्त सेमिनारों, उन्नत डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके लेखा परीक्षा अंतर्दृष्टि साझा करने और माल और सेवा कर (GST) और अन्य लेखा परीक्षा क्षेत्रों में दूरस्थ लेखा परीक्षा जैसे अभिनव तरीकों को शुरू करने सहित पहलों को लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य लेखा परीक्षा और कर प्रक्रियाओं को आधुनिक और सुव्यवस्थित करना है।

6. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कर विवाद समाधान को कारगर बनाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का शुभारंभ किया।

24 सितंबर, 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई

दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का उद्घाटन किया। इस कदम का उद्देश्य GST अपीलों के लिए एक समर्पित, प्रौद्योगिकी-संचालित मुकदमेबाजी मंच की स्थापना करके भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को मज़बूत करना है।

• GSTAT को GST अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अपीलीय मंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे पूरे देश में विवाद समाधान में स्थिरता, विश्वसनीयता और पूर्वानुमान में सुधार होगा।

• न्यायाधिकरण को शब्दजाल-मुक्त निर्णयों, सरलीकृत चेकलिस्ट और प्रारूपों, "डिजिटल-बाय-डिफॉल्ट" फाइलिंग, आभासी सुनवाई और लिस्टिंग, सुनवाई और घोषणाओं के लिए समय मानकों पर जोर देना है।

• लॉन्च के साथ ही, GSTAT ई-कोर्ट्स पोर्टल का भी अनावरण किया गया, जिससे ऑनलाइन अपील दायर करना, प्रगति पर नज़र रखना और सुनवाई में डिजिटल रूप से भाग लेना संभव हो गया है। अपीलों को चरणबद्ध तरीके से दायर करने की अनुमति 30 जून 2026 तक है।

Key Points:-

(i) न्यायाधिकरण नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों के माध्यम से कार्य करेगा। संतुलित विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पीठ में दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य (केंद्र और राज्य) होंगे।

(ii) GSTAT से कानूनी अड़चनों को कम करने, मुकदमेबाजी में देरी को सक्रिय रूप से दूर करने और समय पर न्याय और सुचारू नकदी प्रवाह सुनिश्चित करके MSMEs, निर्यातकों और करदाताओं के बीच विश्वास बहाल करने की उम्मीद है। इसे "निष्पक्षता और निश्चितता के लिए एक राष्ट्र, एक मंच" के दृष्टिकोण के तहत GST सुधारों की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है।

INTERNATIONAL

1. राजनाथ सिंह ने मोरक्को की पहली आधिकारिक यात्रा की और रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा अफ्रीका में भारत के पहले रक्षा संयंत्र का उद्घाटन किया।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय (MoD), ने मोरक्को के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री अब्देलतीफ लौदियी के निमंत्रण पर 22 से 23 सितंबर, 2025 तक मोरक्को की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। यह ऐतिहासिक यात्रा किसी भारतीय रक्षा मंत्री की उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र की पहली यात्रा थी, जिसने भारत और मोरक्को के बीच बढ़ते रणनीतिक और रक्षा संबंधों को प्रदर्शित किया।

• रबात में द्विपक्षीय बैठक के दौरान, राजनाथ सिंह और उनके मोरक्को के समकक्ष अब्देलतीफ लौदियी ने रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को संस्थागत रूप दिया गया।

• राजनाथ सिंह ने रबात स्थित भारतीय दूतावास में एक नए रक्षा विंग की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रक्षा कूटनीति को बढ़ाना और मोरक्को के साथ संस्थागत संबंधों को मजबूत करना है।

Key Points:-

(i) एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, राजनाथ सिंह और अब्देलतीफ लौदियी ने संयुक्त रूप से मोरक्को के बेरेचिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) की अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया।

(ii) 20,000 वर्ग मीटर में फैली TASL सुविधा, भारत में स्वदेश विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WhAP) 8×8 वाहनों का उत्पादन करेगी, जिससे यह अफ्रीका में भारत का पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र और मोरक्को में इस तरह की सबसे बड़ी सुविधा बन जाएगी।

BANKING & FINANCE

1. NPCI के NIPL और कतर नेशनल बैंक ने कतर में UPI सेवाएं शुरू कीं, जिससे यह UPI अपनाने वाला 8वां देश बन गया।

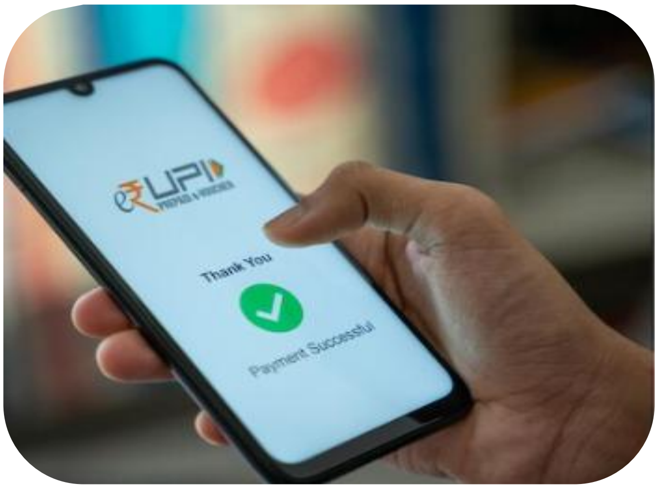

सितंबर 2025 में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने कतर नेशनल बैंक (QNB) के सहयोग से कतर में त्वरित प्रतिक्रिया (QR) आधारित एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) सेवाएँ शुरू कीं। यह सेवा सबसे पहले दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कतर ड्यूटी फ्री में शुरू की गई, जिससे कतर UPI एकीकरण अपनाने वाला आठवाँ देश बन गया।

- **UPI सेवाओं को सक्षम करने वाले समझौते पर NIPL और QNB के बीच 11 जुलाई, 2024 को हस्ताक्षर किए गए। इस प्रणाली को लागू करने वाला पहला व्यापारी दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कतर ड्यूटी फ्री था।**

- **UPI लेनदेन NETSTARS, एक जापानी भुगतान एग्रीगेटर (PA) के माध्यम से सुगम होते हैं, जहाँ भुगतान तुरंत भारतीय रुपये (INR) से कतरी रियाल (QAR) में प्रचलित विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तित हो जाते हैं।**

Key Points:-

(i) UPI सेवा को चरणों में लॉन्च किया गया, जिसकी शुरुआत कतर ड्यूटी फ्री आउटलेट्स से हुई और धीरे-धीरे पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) टर्मिनलों के माध्यम से क्यूएनबी के मर्चेंट नेटवर्क में इसका विस्तार किया गया।

(ii) इस लॉन्च के साथ, कतर UPI को एकीकृत करने वाला दुनिया का आठवाँ देश बन गया, और अब भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ शामिल हो गया है।

(iii) इस पहल से कतर में रहने वाले 8 लाख से ज़्यादा भारतीय प्रवासियों और देश आने वाले भारतीय पर्यटकों को लाभ होगा, जिससे निर्बाध और सुरक्षित सीमा पार लेनदेन को सक्षम बनाकर खुदरा और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

2. RBI ने प्रतिबद्धता वक्तव्य को नवीनीकृत करके FX ग्लोबल कोड के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

सितंबर 2025 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा (FX) वैश्विक संहिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के वक्तव्य (SoC) को नवीनीकृत किया, जिससे FX बाजार में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन को मजबूत किया गया और पारदर्शिता, अखंडता और प्रभावी कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिला।

- **नवीनीकृत प्रतिबद्धता वक्तव्य के अनुसार, RBI एक बाजार भागीदार के रूप में कार्य करता है, जैसा कि FX ग्लोबल कोड के तहत परिभाषित किया गया है।**
- **केंद्रीय बैंक ने अपनी सभी FX बाजार गतिविधियों को संहिता में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप सख्ती से संचालित करने का वचन दिया है, जिससे थोक FX व्यापार में नैतिक और मानकीकृत प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके।**
- **FX ग्लोबल कोड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों का एक समूह है जिसे थोक विदेशी मुद्रा बाजार की अखंडता, पारदर्शिता और प्रभावी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**

Key Points:-

(i) FX ग्लोबल कोड केंद्रीय बैंकों और वैश्विक बाजार सहभागियों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से विकसित किया गया था, जो सामूहिक अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाता है। एफएक्स बाजार आचरण के लिए सुसंगत वैश्विक मानकों को स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों में विश्वास बढ़ाने के लिए इसे पहली बार 2017 में प्रकाशित किया गया था।

(ii) वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति (GFXC), जो FX ग्लोबल कोड को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है, ने इसके प्रकाशन के बाद से दो बार इसकी समीक्षा की है।

(iii) पहली समीक्षा जुलाई 2021 में हुई, उसके बाद दिसंबर 2024 में दूसरी समीक्षा की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संहिता विकसित बाजार प्रथाओं और नियामक मानकों के साथ अद्यतन बनी रहे।

3. SEBI ने 2025 संशोधन के माध्यम से कस्टोडियन के लिए न्यूनतम निवल संपत्ति की आवश्यकता को बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया।

सितंबर 2025 में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सेबी (कस्टोडियन) विनियम, 1996 में संशोधन किया, जिससे कस्टोडियन के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता 50 करोड़ रुपये से बढ़कर 75 करोड़ रुपये हो गई। इस कदम का उद्देश्य भारत में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मज़बूत करना और कस्टोडियन के शासन एवं परिचालन मानकों को बेहतर बनाना है।

• संशोधित विनियमों को अब 'SEBI (कस्टोडियन) (संशोधन) विनियम, 2025' के रूप में जाना जाता है। सेबी ने कहा है कि प्रावधान आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के छह महीने बाद प्रभावी होंगे, जिससे कस्टोडियन को नए मानदंडों का पालन करने के लिए एक संरचित समयरेखा मिलेगी।

• मौजूदा संरक्षकों को नए नियमों के लागू होने के तीन साल के भीतर 75 करोड़ रुपये की संशोधित निवल संपत्ति की आवश्यकता को पूरा करना होगा। सेबी ने स्पष्ट किया है कि संरक्षक कार्यों के लिए समर्पित वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु इस पूंजी को अन्य व्यावसायिक आवश्यकताओं से अलग रखा जाना चाहिए।

Key Points:-

(i) नए विनियमों के तहत, संरक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक मजबूत शासन संरचना बनाए रखें, व्यापक जोखिम प्रबंधन नीतियों को लागू करें, और पर्याप्त तकनीकी क्षमता के साथ-साथ स्केलेबल बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करें।

(ii) संशोधित विनियम संरक्षकों को उनकी योग्यता, क्षमता या उपलब्धियों के बारे में मौखिक या लिखित रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण बयान देने से रोकते हैं।

(iii) इसके अतिरिक्त, संरक्षकों को चोरी, धोखाधड़ी, पेशेवर कदाचार या अन्य परिचालन जोखिमों से उत्पन्न वित्तीय हानि को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय एवं परिचालन उपायों को लागू करना होगा।

MOUs and Agreement

1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने NCS पोर्टल के माध्यम से युवा रोजगार बढ़ाने के लिए ज़ेप्टो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

24 सितंबर, 2025 को, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ज़ेप्टो के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है। इस समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

• मंत्रालय और ज़ेप्टो के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ज़ेप्टो की नौकरी पोस्टिंग को एनसीएस पोर्टल के साथ एकीकृत करना है, जिससे नौकरी चाहने वालों को शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों तक पहुंचने के लिए एक संरचित मंच प्रदान किया जा सके।

• ज़ेप्टो ने समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान 10,000 नौकरी पोस्टिंग प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें गिग और पूर्णकालिक भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में युवाओं, महिलाओं और पहली बार नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

• अपनी स्थापना के बाद से, NCS पोर्टल ने लगभग 7.5 करोड़ रिक्तियों को जुटाया है और नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के बीच एक सेतु का काम किया है। 52 लाख से ज़्यादा पंजीकृत नियोक्ताओं के साथ, यह प्लेटफ़ॉर्म रोज़गार संबंधी सेवाओं के लिए एक व्यापक समाधान बन गया है।

Key Points:-

(i) मंत्रालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य उन्नत डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करके NCS पोर्टल को और मज़बूत बनाने की योजना बना रहा है। इन सुधारों का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को उनके स्थान और योग्यता के आधार पर अनुकूलित अवसर प्रदान करना है, जिससे नौकरी-मिलान प्रक्रिया की दक्षता में सुधार होगा।

(ii) ज़ेप्टो के साथ यह साझेदारी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए मंत्रालय के चल रहे प्रयासों में सहायक होगी।

(iii) पिछले वर्ष के दौरान, अमेज़न, स्विगी, रैपिडो और क्विकर जॉब्स जैसे संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे सामूहिक रूप से NCS पोर्टल पर लगभग पांच लाख रिक्तियां उपलब्ध हुई हैं।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. ACC ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डीएमए के सचिव के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ा दिया।

सितंबर 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने रक्षा मंत्रालय (MoD) के अंतर्गत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के सचिव के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया। यह विस्तार उनके मूल कार्यकाल 30 सितंबर 2025 को समाप्त होने से पहले ही स्वीकृत कर दिया गया था।

- **जनरल अनिल चौहान को 1981 में भारतीय सेना में कमीशन दिया गया था। अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रमुख कमांड और स्टाफ पदों पर कार्य किया है, तथा विविध सैन्य अभियानों में असाधारण नेतृत्व और रणनीतिक विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है।**

- **28 सितंबर 2022 को CDS का पदभार ग्रहण करने के बाद से, जनरल चौहान ने तीनों सेनाओं के एकीकरण को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच परिचालन तालमेल बढ़ाने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड के कार्यान्वयन सहित प्रमुख सैन्य सुधारों का भी नेतृत्व किया है।**

Key Points:-

(i) जनरल चौहान की अनुकरणीय सेवा को कई पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता दी गई है, जिसमें 2020 में परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), 2018 में उत्तम युद्ध सेवा पदक (UYSM), 2015 में अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM), 2011 में सेना पदक (SM), और 2011 में विशिष्ट सेवा पदक (VSM) शामिल हैं।

(ii) ACC द्वारा उनके कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय उनके नेतृत्व और रणनीतिक दृष्टि में सरकार के विश्वास को रेखांकित करता है, जो सैन्य आधुनिकीकरण और परिचालन तैयारियों के महत्वपूर्ण दौर में भारत के रक्षा सुधारों और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय में निरंतरता सुनिश्चित करता है।

AWARDS

1. विराट कोहली ने क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2024 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा।

सितंबर 2025 में, अमेरिकी वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म क्रोल ने अपनी रिपोर्ट का वार्षिक संस्करण 'क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2024' जारी किया। इस रिपोर्ट में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 231.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बताया गया है, जो 2023 की तुलना में 2% की वृद्धि दर्शाता है। साथ ही, इसमें भारत के शीर्ष 25 फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों की रैंकिंग और ब्रांड वैल्यूएशन का विस्तृत विवरण दिया गया है।

- **विराट कोहली 231.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ पहले स्थान पर बने रहे, जबकि प्रसिद्ध अभिनेता रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर रहे। बॉलीवुड स्टार और पद्म श्री पुरस्कार विजेता शाहरुख खान लगातार दूसरे साल तीसरे स्थान पर बने रहे, जो भारत की प्रमुख हस्तियों के बीच लगातार ब्रांड पावर को दर्शाता है।**

- **कुल मिलाकर, भारत की शीर्ष 25 हस्तियों का 2024 में कुल ब्रांड मूल्यांकन 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करता है।**

Key Points:-

(i) आलिया भट्ट इस सूची में सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बनकर उभरीं, 116.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ चौथे स्थान पर रहीं। यह 2023 में उनकी तीसरे स्थान की रैंकिंग से सुधार दर्शाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके बढ़ते प्रभाव और विज्ञापन क्षमता को दर्शाता है।

(ii) कई मशहूर हस्तियों ने 2024 में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया: रश्मिका मंदाना 20वें से 15वें (58.9 मिलियन अमरीकी डॉलर), कृति सनोन 27वें से 19वें (44.8 मिलियन अमरीकी डॉलर), तमन्ना भाटिया 28वें से 21वें (40.4 मिलियन अमरीकी डॉलर) और क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह 41वें से 22वें (38.1 मिलियन अमरीकी डॉलर) स्थान पर पहुंच गईं, जो ब्रांड की दृश्यता और विपणन क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है।

(iii) पहली बार, भारतीय अभिनेत्री अनन्या पांडे ने 35.2 मिलियन अमरीकी डालर के ब्रांड मूल्यांकन के साथ 25वें स्थान पर शीर्ष 25 सेलिब्रिटी सूची में प्रवेश किया, जो 2023 में 46वें स्थान से ऊपर है, जो भारतीय हस्तियों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता और व्यावसायिक अपील का संकेत है।

2. DGCA को प्रभावी विमानन सुरक्षा निरीक्षण के लिए ICAO परिषद अध्यक्ष का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

सितंबर 2025 में, भारत के विमानन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को प्रतिष्ठित

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) परिषद अध्यक्ष प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान एक प्रभावी विमानन सुरक्षा निगरानी प्रणाली स्थापित करने और वैश्विक विमानन मानकों के अनुरूप ढलने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।

• यह प्रमाण पत्र कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित आईसीएओ सभा के 42वें सत्र के दौरान DGCA के महानिदेशक (DG) फैज़ अहमद किदवई को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विमानन सुरक्षा निगरानी में भारत की उपलब्धियों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है।

• ICAO परिषद अध्यक्ष प्रमाणपत्र विमानन सुरक्षा बढ़ाने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

Key Points:-

(i) ICAO परिषद अध्यक्ष प्रमाणपत्र 'कोई देश पीछे न छूटे' पहल का समर्थन करने के लिए बनाया गया था, जिसका उद्देश्य देशों को मजबूत विमानन सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली विकसित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के पालन में सुधार करने में सहायता करना है।

(ii) यह प्रमाणपत्र ICAO यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम सतत निगरानी दृष्टिकोण (USOAP CMA) के परिणामों के आधार पर प्रदान किया जाता है। यह ऑडिट किसी देश द्वारा आईसीएओ के मानकों और अनुशंसित प्रथाओं (SARPs) के अनुपालन का आकलन करता है, जिससे सुरक्षा नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

(iii) यह मान्यता प्राप्त करने से भारत की वैश्विक विमानन प्रतिष्ठा मजबूत होती है, सुरक्षा प्रोटोकॉल में निरंतर सुधार को प्रोत्साहन मिलता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित और विश्वसनीय नागरिक विमानन परिचालन को बढ़ावा देने में देश के नेतृत्व का प्रदर्शन होता है।

IMPORTANT DAYS

1. भारत 23 सितंबर, 2025 को 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया।

निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेद के योगदान को उजागर करने के लिए 23 सितंबर 2025 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 2025 में इस दिवस का 10वाँ संस्करण मनाया गया, जिसे "लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद" थीम के तहत मनाया गया।

• आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) ने 2016 में घोषणा की थी कि आयुर्वेद को स्वास्थ्य सेवा में मुख्यधारा में लाने के लिए धन्वंतरि जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला समारोह 28 अक्टूबर 2016 को आयोजित किया गया था।

• पहले धनतेरस (प्रत्येक वर्ष बदलती तिथि के साथ) पर मनाया जाता था, भारत सरकार ने मई 2025 में आयुर्वेद दिवस के लिए 23 सितंबर को स्थायी तिथि के रूप में निर्धारित किया।

Key Points:-

(i) 2025 का संस्करण 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के

रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मानव कल्याण और पर्यावरणीय सद्भाव दोनों के लिए आयुर्वेद को स्थायी स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोणों में एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

(ii) 23 सितंबर 2025 को, आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) के तहत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (CARI) ने इस दिवस को मनाने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए।

(iii) आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), गोवा में 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने में आयुर्वेद की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

2. विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 विश्व स्तर पर 25 सितंबर को मनाया गया।

विश्व फार्मासिस्ट दिवस (WPD) 2025, 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया गया ताकि दवा विशेषज्ञों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सुरक्षित समुदायों में योगदानकर्ताओं के रूप में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सके। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल फेडरेशन (FIP) की वर्षगांठ का भी स्मरण कराता है।

- **2025 का विषय था "स्वास्थ्य के बारे में सोचें, फार्मासिस्ट के बारे में सोचें", जिसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित दवा उपयोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्टों के योगदान पर जोर दिया गया।**

- **2025 के स्मरणोत्सव का विषय था "स्वास्थ्य के बारे में सोचें, फार्मासिस्ट के बारे में सोचें", जो दुनिया भर में प्रभावी स्वास्थ्य सेवा वितरण, तर्कसंगत दवा उपयोग और मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुनिश्चित करने में फार्मासिस्ट की भूमिका को रेखांकित करता है।**

- **WPD की अवधारणा को पहली बार 2009 में इस्तांबुल, तुर्की में FIP परिषद की बैठक के दौरान तुर्की फार्मासिस्ट एसोसिएशन (TPA) द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसे प्रतिवर्ष मनाए जाने के लिए FIP परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था।**

Key Points:-

(i) प्रथम विश्व औषधि दिवस 25 सितम्बर 2010 को मनाया गया। यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि यह 25 सितम्बर 1912 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय औषधि महासंघ (एफ.आई.पी.) का स्थापना दिवस है।

(ii) वित्त वर्ष 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) में, भारत का दवा बाज़ार 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। 7.8% की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर के साथ, इस उद्योग के 2030 तक 130 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

(iii) भारत दवा उत्पादन में मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है, और दुनिया की 20% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। इसके अलावा, यह UNECEF के टीकों का 55-60%, विश्व स्वास्थ्य संगठन की DPT मांग का 99%, BCG टीकों का 52% और खसरे के टीकों का 45% योगदान देता है।

3. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस 2025 मनाया गया।

भारतीय जनसंघ (BJS) के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 25 सितंबर को पूरे भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 2025 का यह दिवस उनकी 109वीं जयंती का प्रतीक है।

- **अंत्योदय शब्द अंत्य (सबसे गरीब) और उदय (उन्नति) से बना है, जो सबसे गरीब व्यक्ति के उत्थान और सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो अंत्योदय दिवस का सार है।**

- **25 सितंबर 2014 को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के उपलक्ष्य में, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 25 सितंबर को प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।**

Key Points:-

(i) अंत्योदय दिवस का पहला आयोजन 25 सितंबर 2014 को हुआ, जिससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के दृष्टिकोण को सम्मानित करने की परंपरा शुरू हुई।

(ii) पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनके एकात्म मानववाद के दर्शन और सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर उनके ध्यान के लिए याद किया जाता है, जो भारत में अंत्योदय से संबंधित पहलों को प्रेरित करता रहा है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. DRDO और SFC ने अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-प्राइम मिसाइल का रेल-आधारित प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया।

सितंबर 2025 में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA) की सैन्य शाखा स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड (SFC) के सहयोग से, अब्दुल कलाम द्वीप (ओडिशा तट) से रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर (RBML) से इंटरमीडिएट रेंज अग्नि-प्राइम (Agni-P) मिसाइल का पहला सफल परीक्षण पूर्ण संचालन स्थितियों में किया।

- **यह परीक्षण भारत के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से एकीकृत, विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर (RBML) का उपयोग करते हुए पहली बार किया गया। यह सफलता मोबाइल मिसाइल तैनाती प्रणाली के विकास में एक मील का पत्थर है।**

- **परीक्षण के दौरान मिसाइल की उड़ान-पथ को सटीक रूप से ट्रैक किया गया और यह एक 'टेक्स्टबुक लॉन्च' साबित हुआ। सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया गया, जिससे रेल-आधारित मिसाइल**

प्रणालियों को भारत की रणनीतिक शस्त्रागार में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

Key Points:-

(i) RBML को भारत के विशाल रेल नेटवर्क पर बिना किसी पूर्व-शर्त के संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह त्वरित प्रतिक्रिया समय, बेहतर गतिशीलता और कम दृश्यता जैसे लाभ प्रदान करता है, जिससे भारत की सेकंड-स्ट्राइक परमाणु क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया जा सकता है।

(ii) RBML को स्वतंत्र प्रक्षेपण क्षमता, अत्याधुनिक संचार प्रणालियों और मजबूत सुरक्षा तंत्र जैसी उन्नत विशेषताओं से सुसज्जित किया गया है, जो विभिन्न परिस्थितियों में परिचालन तत्परता सुनिश्चित करता है।

(iii) अग्नि-पी एक स्वदेशी रूप से विकसित, दो-स्तरीय, कैनिस्टरयुक्त, ठोस ईंधन वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर है, जो भारत की प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक लचीलापन और जीवंतता प्रदान करती है।

OBITUARY

1. प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार एस.एल. भैरप्पा का 24 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में निधन हो गया।

24 सितंबर 2025 को, प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार, दार्शनिक और पटकथा लेखक संतेशिवरा लिंगन्नैया (एस.एल.) भैरप्पा का बेंगलुरु, कर्नाटक में निधन हो गया। 20 अगस्त 1931 को कर्नाटक के हासन जिले के संतेशिवरा गाँव में जन्मे, वे भारतीय साहित्य के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे।

- **एस.एल. भैरप्पा ने एक अग्रणी कन्नड़ लेखक के रूप में स्वयं को स्थापित करने से पहले अकादमिक करियर अपनाया, उनके लेखन में दर्शन, इतिहास और सौंदर्यशास्त्र की गहरी जड़ें थीं।**
- **अपनी छह दशक लंबी साहित्यिक यात्रा के दौरान, उन्होंने 25 उपन्यासों के साथ-साथ कई लघु कथाएँ और निबंध लिखे, जिनमें परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष की पड़ताल की गई।**
- **उनकी कुछ सबसे प्रशंसित कृतियों में वंशवृक्ष, दातु, तंतु, पर्व, गृहभंगा, मंदरा, अन्वेषण, सार्थ, नैनेरालु, अंगु, धर्मश्री, दूरसारड्डे और वोटिंग शामिल हैं। इनमें से कई कार्यों को बाद में फिल्मों और टेलीविजन में रूपांतरित किया गया।**

Key Points:-

(i) भैरप्पा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के कुछ सर्वोच्च साहित्यिक और नागरिक पुरस्कार मिले, जिनमें सरस्वती सम्मान (2010), साहित्य अकादमी फेलोशिप (2015), पद्म श्री (2016) और पद्म भूषण (2023) शामिल हैं।

(ii) उन्हें कई अकादमिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें गुलबर्गा विश्वविद्यालय (2007), मैसूर विश्वविद्यालय (2015) और कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय (2020) से मानद डॉक्टरेट की उपाधियाँ शामिल हैं। उनकी रचनाओं ने बहस छेड़ी, पीढ़ियों को प्रेरित किया और कन्नड़ तथा भारतीय साहित्य में उनका योगदान कालजयी बना रहा।

Static GK

Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)	महानिदेशक (DG): डॉ. एन. कलैसेलवी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Comptroller and Auditor General of India (CAG)	उद्घाटनकर्ता: वी. नरहरि राव	स्थापित: 1858
Morocco	प्रधान मंत्री (PM) : अजीज अखन्नौच	राजधानी : रबात
Qatar	PM : शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी	राजधानी : दोहा
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
SEBI	अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे	मुख्यालय: मुंबई
Appointments Committee of the Cabinet (ACC)	स्थापना: 1950	मुख्यालय: नई दिल्ली
DRDO	अध्यक्ष: समीर वी. कामत	मुख्यालय: नई दिल्ली
International Pharmaceutical Federation (FIP)	CEO : डॉ. कैथरीन डुग्गन	मुख्यालय : द हेग, नीदरलैंड